राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 61 | जौनपुर मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

करूर भगदड़ कांड सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के करूर में तमिल अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (ष्टक्चढ़ढ़) को सौंप दी है। कोर्ट ने इस मामले में 10 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सीबीआई जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का भी गठन किया है। यह समिति पूरी जांच प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगी। यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेता उमा आनंदन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि यह दुखद घटना 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में हुई थी, जहां अभिनेता से राजनेता बने विजय की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था।

स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को हीरोपंती पड़ी महंगी

रांची, (एजेंसी)। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाड़ियों के काफिले के बीच चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने उन पर ?3650 का जुर्माना लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में कृष अंसारी सनरूफ से बाहर खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए उपायुक्त (डीसी) मंजूनाथ भजंत्री ने स्वतरू संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट कर जिला परिवहन पदाधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और रांची पुलिस को टैग कर रिपोर्ट भी मांगी। प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की विभिन्न धाराओं, जिनमें असुरक्षित ड्राइविंग और सीट बेल्ट उल्लंघन जैसे नियम शामिल हैं, के तहत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के बेटे पर ?3650 का चालान काटा है। यह पहली बार नहीं है जब मंत्री पुत्र कृष अंसारी इस तरह चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी उनका अस्पतालों का श्दौराच्य करने का वीडियो वायरल हुआ था। एक वीडियो में वह रिम्स में मरीजों से उनका हालचाल पूछते दिखे थे, जबकि उनके साथ मौजूद लोग उन्हें मंत्री जी का बड़ा बेटा बताकर समस्याएं रखने को कह रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'इन्वेस्ट यूपी' के पुनर्गठन प्रस्ताव को दी मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न 'इन्वेस्ट यूपी' शासी निकाय की पहली बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। साथ ही प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें कहा गया कि नए ढांचे के तहत कपड़ा, मोटर वाहन एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक एवं सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में उपग्रह निवेश संवर्धन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य 'इन्वेस्ट यूपी' को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता–आधारित और निवेशक–केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है। बैठक में 11 महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक पदों पर कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पीसीएस संवर्ग) को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करनेको मंजूरी दी गई। इसके अलावा भूमि बैंक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें दो पीसीएस अधिकारी (उपजिलाधिकारीध्अपर जिलाधिकारी स्तर) तैनात होंगे। बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने बीते कुछ वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024–25 में करीब 4,000 नई फैक्टरी स्थापित हुईं, जिससे राज्य में इनकी कुल संख्या 27,000 हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन' (रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म) मंत्र के सफल क्रियान्वयन से राज्य के औद्योगिक परिवेश में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है।

नए आपराधिक कानून से देरी से न्याय खत्म, अमित शाह बोले– 2027 तक बड़ा बदलाव

नई दिल्ली , (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि नए कानून समय पर, सुलभ और सरल न्याय सुनिश्चित करेंगे क्योंकि ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को दंड के बजाय न्याय के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि भारत की न्यायिक प्रणाली ने न्याय में देरी करने की अपनी एक पहचान बना ली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नया आपराधिक कानून इसमें बदलाव लाएगा।

अमित शाह ने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली समय पर न्याय न देने के लिए बदनाम हो गई है। मुझे राजस्थान के लोगों को यह विश्वास दिलाते हुए पूरा विश्वास है कि तीन आपराधिक न्याय कानून समय पर, सुलभ और सरल न्याय सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन को आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। लेकिन इन कानूनों के लागू होने के साथ ही न्याय की सुगमता में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। शाह ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दंड के बजाय न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। इसे पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और गृह मंत्रालय सभी राज्यों को सहायता और अनुवर्ती मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के भाजपा के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने बताया कि 2027 के बाद दर्ज की गई किसी भी प्राथमिकी पर तीन साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।

बिहार चुनाव एनडीए के छोटे दल 41 सीटों पर आजमाएंगे किस्मत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फार्मूले की घोषणा की, जिसमें 243 सीटों में से 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल–यूनाइटेड (जेडी–यू) को आवंटित की गईं। इसके अलावा, शेष सीटें लोजपा–रामविलास, एचएएम और आरएलएम सहित छोटे सहयोगियों को दी गईं। सुप्रीम कोर्ट आज स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनाएगा फैसला इस समझौते के तहत, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) 6–6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, लोजपा–रामविलास गया, फतुहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मस्थान बख्तियारपुर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। जितना पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ होगारू सीएम रेखा गुप्ता इस बीच, दो चरणों में होने वाले बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए भाजपा कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक के बाद जल्द ही एनडीए की सीटों के बंटवारे की पूरी व्यवस्था की औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। सीट–बंटवारे के समझौते से जुड़े शीर्ष सूत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, एलजेपी के 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, जिनमें बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसरा, राजा पाकर, लालगंज, हायाघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगिआंव, ओबरा, अरवल, गया।

पीएम मोदी जल्द को एनडीए के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही वह मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था, वहीं बारिश कीश इसके साथ कार्यकर्ता अपने सुझाव पीएम मोदी के साथ नमो ऐप के जरिए साझा कर सकते हैं। सुझाव देने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से नमो ऐप के माध्यम से संवाद करने का सीधा मौका भी मिल सकता है। पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार में भाजपा–एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। कहा – सहयोगी दलों को हैसियत दिखाकर

घुटनों पर लाने का किया काम उन्होंने आगे लिखा, मेरा आग्रह है, आप सभी 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान से जुड़ें और अपने सुझाव आज ही साझा करें। चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर मैं सीधे उनके साथ चर्चा भी करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए और इंडी गठबंधन चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके साथ ही दोनों ही गठबंधन प्रदेश में अपनी–अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा वे जनता को लुभाने के लिए कई बड़े–बड़े वादे भी कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कल साफ हो जाएगी पूरी तस्वीर उल्लेखनीय है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

गडकरी करेंगे 'एलिवेटेड कॉरिडोर सहित 2000 करोड़ की हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास

नई दिल्ली , (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अपने दौरे के दौरान यहां इंदिरा गांधी स्क्वायर और राजीव गांधी स्क्वायर को जोड़ने वाले 436 करोड़ रुपये की लागत वाले चार किलोमीटर लंबे 'एलिवेटेड कॉरिडोर' की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के 38 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले पुडुचेरी–पूंडियनकुप्पम खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे 1,588 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री ई वी

वेलु, पुडुचेरी के मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के मद्देनजर शहर की यातायात पुलिस ने सोमवार को वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरे के दौरान, श्री गडकरी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी चौकों को जोड़ने वाले 436 करोड़ लागत के ग्रेड सेपरेटरध्एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) नित्या राधाकृष्णन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने आगमन के बाद, मंत्री सड़क मार्ग से कोक्कू पार्क के निकट कृषि मैदान में आयोजित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। उनके उसी दिन शाम को लौटने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के मद्देनजर शहर की यातायात पुलिस ने सोमवार को वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरे के दौरान, श्री गडकरी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी चौकों को जोड़ने वाले 436 करोड़ लागत के ग्रेड सेपरेटर/एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) नित्या राधाकृष्णन की ओर से जारी ।

आरएसएस के शिविरों में बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण – प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। केरल के 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदखुशी की। इस कदम को उठाने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि यह तक कहा कि वो आरएसएस के कारण ही खुदखुशी कर रहे हैं। युवक ने आरएसएस पर शारीरिक शोषण के आरोप भी लगाए। इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म श्ग्श पर लिखा–आरएसएस को इन आरोपों की पूरी जाँच होनी चाहिए। अपने आत्महत्या संदेश में आनंदू अजी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के कई सदस्यों ने उनके साथ बार–बार दुर्व्यवहार किया। दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं रू उदित राज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे

अकेले पीड़ित नहीं हैं और आरएसएस के शिविरों में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। अगर यह सच है, तो यह भयावह है। पूरे भारत में लाखों बच्चे और किशोर इन शिविरों में जाते हैं। आरएसएस नेतृत्व को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। लड़कों का यौन शोषण लड़कियों के यौन शोषण जितना ही व्यापक है। इन अवर्णनीय रूप से जघन्य अपराधों के बारे में चुप्पी तोड़नी होगी।

सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ की स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ 13 अक्टूबर को इस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाएगी। याचिकाओं में घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं उदित राज जहां अभिनेता–राजनीतिज्ञ विजय की पार्टी टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है, वहीं भाजपा नेता उमा आनंदन सहित कई अन्य लोगों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। यह त्रासदी हाल के वर्षों में तमिलनाडु में भीड़ नियंत्रण की सबसे गंभीर विफलताओं में से एक मानी जा रही है, जिसने राजनीतिक आयोजनों में सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।मिजोरम और जम्मू–कश्मीर में उपचुनाव की घोषणा की, 11 नवंबर को होगा मतदान इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी आसरा गर्ग की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया था। 3 सितंबर को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि घटना के बाद नेताओं और आयोजकों ने अपने समर्थकों को घटनास्थल पर छोड़ दिया। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने कहा था, "चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यक्रम आयोजक और पार्टी के नेता हादसे के बाद स्थल से फरार हो गए।

कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी

देहरादून, (एजेंसी)। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने निर्णय लिया। वहीं, कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शेष 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर

होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है। की रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल है। में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

संपादकीय

आखिर तक पर्दादारी!

सवाल नहीं उठते, अगर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की भावना के अनुरूप जारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या काटने की वजह भी बता दी होती। मगर आयोग ने यह नहीं किया, तो बात फिर अदालत पहुंची। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के क्रम में निर्वाचन आयोग ने ऐसी हर कोशिश की है, जिससे लोग उसके इरादे पर शक करें! उसने हर कदम पर पारदर्शिता से परहेज किया। उनमें से कई कोशिशें नाकाम हुईं, तो उसका पूरा श्रेय सर्वोच्च न्यायालय और जागरूक नागरिकों को दिया जाएगा। पहले की सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए या जिनके जोड़े गए, उनके बारे में निर्वाचन आयोग पूरी सूचना सार्वजनिक करे। कोर्ट के सख्त रुख के बाद आयोग ने नाम काटने की वजह बताते हुए 66 लाख से अधिक उन लोगों की लिस्ट जारी की, जिनके नाम नई अंतरिम सूची में नहीं थे। अंतरिम सूची पर दावा और आपत्ति की अवधि पूरी होने के बाद आयोग ने अंतिम सूची जारी की, तो सामने आया कि तीन लाख 66 ऐसे नाम गायब हो गए हैं, जो अंतरिम सूची में थे। इसके अलावा साढ़े 21 लाख नए नाम शामिल किए गए। यह सवाल जायज है कि एसआईआर के दरम्यान उपरोक्त 3.66 लाख नाम सूची में रखने लायक समझे गए थे, तो बाद में उन्हें क्यों काटा गया? और इतनी बड़ी संख्या में नए नाम कहां से आ गए? ये सवाल नहीं उठते, अगर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की भावना के अनुरूप जारी सूची में नाम जोड़ने या काटने की वजह भी एक कॉलम में बता दी होती। मगर आयोग ने फिर डंडी मारने की कोशिश की, तो बात फिर अदालत पहुंची। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अंतिम सूची से भ्रम पैदा हुआ है। उसने नए काटे या जोड़े गए नामों की पहचान बताने का निर्देश आयोग को दिया है। तो अब शायद आयोग उन नामों की पहचान के साथ–साथ उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने या काटने के कारण बताएगा। लेकिन इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया और आयोग के तौर–तरीकों को लेकर समाज के एक हिस्से में नए सिरे से संदेह पैदा हो चुके हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया पर आंच आ सकती है। बेहिचक कहा जा सकता है कि इसके लिए पूरी तरह निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है।

धौंस-धमकान की नीति ट्रंप के लिए होगी आत्मघाती

राजेन्द्र

धमकाने और धौंस की नीति पर चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी झूठी चौधराहट और खनिजों के चक्कर में लगता है दुनिया के देशों में अमेरिकी विरोधियों की बड़ी फौज ही तैयार करते जा रहे हैं। शांति के नोबल पुरस्कार का ट्रंप का सपना धरा का धरा ही रह गया है और अब 30 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त 100 प्रतिषत और यानी कि 130 प्रतिशत टैरिफ लगाकर चीन के खिलाफ भी आर्थिक क्षेत्र में खुली जंग ही छेड़ दी है। कनाडा को अमेरिका का नया राज्य बनाने और रुस यूक्रेन युद्ध के पीछे के अमेरिकी एजेंडे को आज दुनिया क देश समझ ही चुके हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ डिनर के माध्यम से अमेरिका के गिरते स्तर को दुनिया क देश देख ही चुके हैं। भारत जैसे देश से पंगा लेना सबके सामने हैं। पाकिस्तान पर भी खनिजों के चक्कर में डोरे ड़ाले जा रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप का रवैया जिस तरह का दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद देखने को मिल रहा है वह गली मौहल्ले के गुंडे मवाली जैसा ही दिखाई देने लगा है। दुनिया के देशों को धमकाना जैसे ट्रंप का काम ही हो गया हो। दुनिया के देशों में युद्ध समाप्त कराने का झूठा तमगा पहनने के प्रयास और शांति के नोबल पुरस्कार के लिए नोबल संस्था तक को धमकाने के कुत्सित प्रयास से ट्रंप स्वयं और अमेरिका दोनों की ही हेठी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। चीन से पहले भारत पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने और वीजा नियमों में बदलाव से अपने ही पांवों में ठोकर मारी है। हालांकि भारत किसी भी तरह के ट्रंप के दबाव में नहीं आया और सबसे बड़ी तोहिन तो यह रही कि भारत ने इस पर प्रतिक्रिया तक व्यक्त करने की जेहमत नहीं उठाई जिसके कारण अमेरिका का तमतमाना लाजिमी भी हो जाता है। अमेरिका ने भारत पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद सोचा था कि भारत घुटनों के बल आ जाएगा पर हुआ इसका उल्टा ही और भारत ने नये बाजार की संभावनाएं तलाशना आंरभ कर दिया। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अब चीन पर अमेरिकी टैरिफ वार का लगता है भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत की निर्यात की संभावनाओं को पर लगने के अधिक आसार हो जाएंगे। स्वाभाविक है चीन के उत्पाद महंगे हो जाएंगे और भारतीय उत्पाद कपड़ा, हैण्डिक्राफ्ट, खिलौने आदि आदि तुलनात्मक रुप से सस्ते होंगे तो भारतीय उत्पादों की मांग कम होने के स्थान पर बढ़ेंगी ही। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ वार अमेरिका पर ही उल्टा पड़ना है। आज अमेरिका भारतीय प्रतिभाओं का लाभ उठा रहा है पर नए वीजा नियमों और विदेशियों को पलायन करने के बाध्यकारी आदेशों से अमेरिका आने वाले समय में शून्यता की और ही बढ़ेगा। लगता तो यहां तक है कि आने वाले समय में अमेरिका विदेशी प्रतिभाओं से शून्य हो जाएगा और अमेरिकी प्रतिभाओं को आगे आना इतना आसान भी नहीं होगा। इधर ट्रप के व्यवहार के चलते श्वेत–अश्वेत की खाई चौड़ी होती जा रही है। बीसवीं सदी के अंत में दुनिया के देशों में विश्वग्राम का सपना देखा था, इस दिशा में दुनिया के देश आगे भी बढ़े थे और फिर संचार क्रान्ति ने तो दुनिया के देषों को लगभग विश्वग्राम बना ही दिया पर जिस तरह के हालात ट्रंप जैसे अति महत्वाकांक्षी द्वारा उठाये जा रहे हैं, उससे विश्वग्राम का सपना बीच राह में ही टूटता नजर आने लगा है। एक दूसरे के सहयोग और समन्वय की बात तो ट्रंप ने भुला ही दी है। फिर सबकों एक ही लकड़ी से हांकने की नीति भी आत्मघाती बनती जा रही है। अमेरिका को समझना यह होगा कि आज आप किसी पर टैरिफ का दबाव बढ़ाते हो तो अन्य देशों के लिए राह आसान कर रहे हो। हो यह रहा है कि टैरिफ की मार का सबसे नकारात्मक प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ना है। एक तरफ अमेरिका की जरुरतों को पूरा करने में जुटे विदेशी देषों के उत्पाद महंगे होंगे तो दूसरी और अमेरिकी इकोनोमी पर भी निश्चित रुप से विपरीत प्रभाव पड़ना ही है। आज दूसरे देशों के प्रति निर्भरता बढ़ी है और ऐसे में आगे बढ़ने के लिए दो मोर्चों पर जुटना पड़ता है। पहले तो यह कि दूसरे देशों में आ रहे बदलावों, तकनीक आदि को समझना और फिर उस तकनीक को अपनी जरुरत के अनुसार अपने देश में विकसित करना। अमेरिका दरअसल दूसरों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है पर वह यह भूल रहा है कि इकोनोमी एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ती हैं। देसी–विदेशी मांग को बढ़ाना ही होता है। स्थानीय के साथ ही विदेशों में भी बाजार खोजना होता है। ऐसे में बड़े बड़े व्यापार समझौते देशों के बीच होते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से

व्यापार समझौतों को दरकिनार कर टैरिफ वार और तरह तरह के अवरोध ा खड़े करने के प्रयास किये हैं उनका असर अंततोगत्वा अमेरिकी इकोनोमी पर भी पड़ना ही है। लगता है ट्रंप अमेरिका को आत्मघाती गोल की तरफ ले जा रहा है। दुनिया के देशों को वैश्विक ग्राम की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाना होगा। आज दुनिया और दुनिया के देश कहां खड़े हैं यह कोरोना काल में सबको पता चल चुका है। इसके साथ ही जिस तरह से युद्ध और वैश्विक अशांति के चलते पलायन का दौर चला है उसका खामियाजा फ्रांस सहित योरोपीय देश भुगतने लगे हैं। ऐसे में समय रहते नीतियों मे बदलाव जरुरी हो जाता है। जिस तरह से तकनीक ने एक दूसरे को नजदीक लाने का प्रयास किया है उसे आगे बढ़ाना वैश्विक नेताओं का दायित्व हो जाता है। आज एकला चालो रे की नीति से आगे बढ़ने और कुछ पाने की कल्पना करना बेमानी होगा, यह देर सबेर समझना ही होगा।

जातिवाद का जहर और दलित उत्पीड़न

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कु मार का अंतिम संस्कार इन पंक्तियों के लिखे जाने तक नहीं हो पाया है, वहीं हरियाणा सरकार के दो मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे बड़े अधिकारी पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। इस मामले में हरियाणा सरकार ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया है। आईपीएस अधि ाकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।बता दें कि पूरन कुमार का शव 7 अक्टूबर मंगलवार को उनके घर पर मिला था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। अपनी मौत से पहले दिवंगत अधि ाकारी ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जातिगत प्रताड़ना और अपमान के आरोप उन्होंने लगाए। पूरन कुमार ने लिखा कि 2020 में तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने मेरा उत्पीड़न शुरू किया, हरियाणा कैडर के अन्य अधिकारी आज भी प्रताड़ित कर रहे, तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा ने मुझे छुट्टियां नहीं दीं। मैं अपने बीमार पिता से मिलने तक नहीं जा सका। वर्षों तक मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। मेरे खिलाफ छद्म नामों से दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की गईं। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित और शर्मिंदा किया गया। अपने उत्पीड़न की एक लंबी फेरहिस्त देते हुए पूरन कुमार ने लिखा कि– मैं और अधिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का निर्णय लिया है।यकीन करना मुश्किल है कि 21 वीं का चौथाई हिस्सा निकल गया है और भारत में दलित उत्पीड़न खत्म ही नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि कमजोर वर्गों को शिक्षा की शक्ति से लैस किया जाए, तो उनकी स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन यहां ये तर्क भी नाकाम दिख रहा है। रायबरेली में गरीब हरिओम वाल्मिकी को पीट–पीट कर मारना, देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर जूता फेंकना और फिर सोशल मीडिया पर उसे सही ठहराया जाना और एक पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ लेकिन दलित अधिकारी का उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करना या उससे पहले वैज्ञानिक बनने की चाह रखने वाले छात्र रोहित वेमुला का आत्महत्या करना, तमाम मामले इस बात की गवाही चीख–चीख कर दे रहे हैं कि दलितों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं आ सकता, जब तक इस देश से मनुवादी सोच का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन अभी तो हाल ये है कि मनुस्मृति को ही धर्म बताकर संघ और भाजपा के समर्थकों का बड़ा हिस्सा उसे संविधान में तब्दील करने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने इस बारे में संसद से ही देश को चेतावनी दे दी थी कि भाजपा मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, संविधान को नहीं।लेकिन उनकी बात को राजनीति कहकर टालने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि देश देख रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हो रहे हैं। पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिशें हुईं, लेकिन उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार जो कि खुद 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि, श्पुलिस की एफआईआर में नाम हटाए गए और एससी एसटी एक्ट के सेक्शन कमजोर किए गये।श अमनीत कुमार खुद प्रशासन और कानून की बारीकियों से वाकिफ हैं, इसलिए वे समझ गईं कि आरोपियों को बचाने की कैसी चालाकी चल रही है। अगर उनकी जगह आईपीएस अधि ाकारी की पत्नी साधारण पृष्ठभूमि की होतीं या इस बात को नहीं समझ पाती तो शायद इस मामले में पीड़ित को ही दोषी बताकर मामला दबा दिया जाता।अब तो विपक्ष ने भी इस पर पुरजोर आवाज उठाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिखा, वहीं सोनिया गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर अमनीत कुमार को ही चिऋी लिखी और इस संघर्ष में उनके साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि कैसे आज भी दलितों को मध ययुगीन प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा को इसमें राजनीति नजर आ रही है। क्या भाजपा यह नहीं जानती कि विपक्ष का काम उसकी गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान दिलाना है, बाकी जी हुजूरी का सारा काम मीडिया तो कर ही रहा है, विपक्ष के दल भी अगर ऐसे ही सरकार की चापलूसी करने लगें तो फिर लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या भाजपा यही चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान न रहे। वैसे भी एनसीआरबी का डेटा बताता है– 2013–2023 के बीच दलितों पर अत्याचार 46 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति पर 91प्रतिशत तक बढ़ा है। 2023 में 57,789 दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15,368 मामले फिर मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे भाजपा शासित राज्य है, इसे महज संयोग माना जाए या फिर मनुवादी सोच पर आधारित सरकार और प्रशासन का परिणाम। अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां आज भी ब्राह्मण के आगे देवता लगाकर बात करना समाज को अजीब नहीं लगता। बाबा साहेब अंबेडकर से पहले, उनके काल में और आज तक दलितों की स्थिति समाज में जस की तस है। समस्या शिक्षा की कमी नहीं, नसों में जातिवाद के फैले जहर की है, जो दलितों के लिए उच्च स्थान कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता है।

इतिहास की पुनरावृत्ति, तालिबान से मित्रता विदेशमंत्री जसवंत सिंह

तुहिन

अफगानिस्तान में प्रगतिशील सरकार और अफगानिस्तान की प्रगतिशील ताकतों को खत्म करने के लिए अस्सी के दशक में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पाकिस्तान के सहयोग से इस्लामिक कट्टरपंथियों को हथियारबंद करके और भलीभांति प्रशिक्षित कर तालिबान को तैयार किया। तालिबान ने वामपंथी सरकार के पतन के बाद गृह युद्ध में नॉर्दर्न एलायंस को हराकर काबुल में प्रवेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में 26 साल पहले कंधार में भारत के तत्कालीन विदेशमंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकिल से समझौता किया था। उद्देश्य था– आईसी–415 एयर इंडिया फ्लाइट (जिसे पाक और तालिबान समर्थित आतंकवादियों ने अगवा किया था), के मुद्दे को सुलझाना। इस समझौते के आधार पर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को रिहा किया गया और पाकिस्तान भेजा गया। उस समय भी भाजपा की सरकार थी। 26 साल बाद इसी भाजपा की सरकार ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दी है और हाल ही में दिल्ली में तालिबान के वर्तमान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की और समझौता हुआ। ये तालिबान कौन है?रू अफगानिस्तान में प्रगतिशील सरकार और अफगानिस्तान की प्रगतिशील ताकतों को खत्म करने के लिए अस्सी के दशक में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पाकिस्तान के सहयोग से इस्लामिक कट्टरपंथियों को हथियारबंद करके और भलीभांति प्रशिक्षित कर तालिबान को तैयार किया। तालिबान ने वामपंथी सरकार के पतन के बाद गृह युद्ध में नॉर्दर्न एलायंस को हराकर काबुल में प्रवेश किया। इसके लिए तालिबान ने नॉर्दर्न एलायंस के नेता श्पंजशीर का शेरश अहमद शाह मसूद सहित कई मुजाहिदीन नेताओं की निर्मम हत्या की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे पहले उन्होंने पांचवे अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह और उनके सलाहकारों को काबुल में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूतावास से जबरन निकालकर कुत्ते की तरह मारकर लैंप पोस्ट में लटका दिया। उन्होंने देश में मौजूद संग्रहालयों, अन्य धर्मों से संबंधित तमाम स्मारक मूर्तियों को जिनमें विश्व विख्यात बामियान की बुद्ध मूर्ति (जो यूनेस्को की विश्व विरासत थी), भी शामिल थी, को ध्वस्त कर दिया। तालिबान ने अपने पहले कार्यकाल में (जब तक तालिबान भस्मासुर नहीं बन गया और उनके जन्मदाता अमरीकी साम्राज्यवाद उनसे नाराज नहीं हो गए) 15 अगस्त 2021 में अमेरिका द्वारा उनको काबुल का शासन सौंपने के बाद दूसरे कार्यकाल में घोर प्रगति विरोधी, मध्य युगीन प्रतिक्रियाशील रूढ़िवादी धार्मिक कानूनों और घोर महिला विरोधी कानूनों को लागू किया। तालिबान ने बहुत क्रूर मध्ययुगीन तरीके से अपने विरोधियों, बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों को मार डाला और इस तरह से एक प्रगतिशील शिक्षित अफगानिस्तान को पिछड़ेपन जहालत और बर्बादी में धकेल दिया। जब तक पाकिस्तान के धार्मिक सैन्य केंद्र से इसकी गलबहियां चलती रही तब तक सब ठीक था। अब अफगान तालिबान द्वारा पैदा किए गए तहरीक–ए–तालिबान, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है उससे पाकिस्तान को परेशानी हो रही है।इसलिए अब पाकिस्तान के हुक्मरान और अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों के संबंधों में खटास आ गई है। दूसरी ओर, चूंकि भारत की मोदी सरकार विदेश नीति के मामले में न केवल अपने पड़ोसी देशों से बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों से अलग–थलग पड़ गया है। इसीलिए उसे पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए एक सहयोगी की जरूरत है। भले ही वह घोर धार्मिक कट्टरपंथी प्रगति–विरोधी तालिबान शासक ही क्यों न हो। तालिबान को आतंकवादी जियोनवादी इजरायल और उसके संरक्षक अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा गजा को श्मशान बनाने में या मध्य पूर्व के अन्य देशों में और दुनिया भर में उसके आका अमेरिकी शासकों द्वारा इस्लामोफोबिया के नाम पर शोषण, लूट या दमन से कुछ लेना–देना नहीं है। इसलिए उसको भारत के घोर जन–विरोध ी और मुस्लिम–विरोधी संघ परिवार या उसके मार्गदर्शन में संचालित भाजपा सरकार से हाथ मिलाने में तो खुशी ही होगी । और दूसरी ओर देखिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फासीवादी संगठन क्रस्स् को भी कोई समस्या नहीं है। इस्लाम का झंडा फहराकर देश को मध्य युग में ले जाने वाले तालिबान से मित्रता करने में। कारण यह है कि चाहे अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर बर्बाद करने वाले आतंकवादी तालिबान हो या मनुस्मृति आधारित हिंदुराष्ट्र के नाम पर देश को लूटने वाला संघ परिवार हो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों कॉरपोरेट पूंजीवादी और दुनिया की जनता के दुश्मन नंबर एक अमेरिकी साम्राज्यवाद के अनुगत हैं और घोर प्रगति–विरोधी, समाज–विरोधी और मानवता विरोधी हैं।

नफरत ही खाना, नफरत ही पीना, नफरत रोज बढ़ाना जय भाजपा!

शकील अख्तर

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में केवल पुरुष पत्रकार जाएंगे इस पर मोदी सरकार को कोई आपत्ति नहीं हुई। उल्टा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसमें महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिए जाने का सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गोदी मीडिया और भक्तों, ट्रोलों वाला यह बचकाना तर्क देने लगे कि अपने दूतावास में वे किसे बुलाएं किसे नहीं यह उनका अधिकार है। दलितों के खिलाफ मन में इतना जहर! उन्हें नीचा दिखाने के लिए वे जिन्हें अपना सबसे बड़े नेता मानते हैं उन डॉ. अम्बेडकर को रैलियां निकाल कर अंग्रेजों का गुलाम कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थिति विस्फोटक हो गई है। यहां दिल्ली की तरह एक सामान्य वकील नहीं बल्कि ग्वालियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे अनिल मिश्रा लगातार डॉ. अम्बेडकर को गालियां दे रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई है मगर इसके बावजूद वे न केवल अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि उनके समर्थन में बड़ी तादाद में आ गए उनकी विचारधारा के वकील और राजनीतिक लोग भी अब इसे बढ़ाकर संविधान निर्माता के तौर पर उनका नाम हटाकर वी एन राव का नाम लिखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरक्षण खत्म करने की। देश में नफरत और विभाजन को कहां तक ले आया गया है यह ग्वालियर में अम्बेडकर के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से मालूम पड़ता है। जिन वकीलों ने अम्बेडकर के खिलाफ मुहिम शुरू की है वे अब खुलेआम पुलिस को चौलेंज कर रहे हैं कि अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वाले वकील अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करके दिखाओ! राज्य सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है। प्रशासन ने केवल अभी धारा 144 लगाकर जुलूस प्रदर्शनों पर रोक का इंतजाम किया है। अम्बेडकर देश में हमेशा से दक्षिणपंथियों के निशाने पर रहे हैं।

देश में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं अम्बेडकर की तोड़ी गई हैं। कारण स्पष्ट है अम्बेडकर ने मनुवाद को सीधे चौलेंज किया था। सौ साल होने वाले हैं जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। 1927 में। और इसके बाद संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संविधान में एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। बीजेपी आरएसएस जो कभी सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाई वह दलित पिछड़े आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए तो अम्बेडकर की बात करती है मगर मन से कभी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाती। इसलिए संघ ने उस समय संविधान का विरोध किया था। उस समय संघ के मुखपत्र आर्गनाइजर ने लिखा थारू श्हम संविध ाान को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति ही दुनिया में प्रशंसित है। 1949 में।श यहां इस विरोधाभास को रेखांकित करना भी जरूरी है कि आज उसी प्रतिक्रियावादी सोच के लोग दावा कर रहे हैं कि संविधान अम्बेडकर ने नहीं वीएन राव ने लिखा था। तो अगर राव ने लिखा था जिसे वे ब्राह्मण होने के कारण स्वीकृति और सम्मान दे रहे हैं तो फिर संघ ने इसका विरोध क्यों किया था? मूल समस्या अम्बेडकर के दलित होने से है। बीजेपी आरएसएस के लोग यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कोई दलित इतना विद्वान हो सकता है कि वह संविधान लिखे। आज भी जो सारा आन्दोलन आरक्षण के खिलाफ होता है उसमें यही कहा जाता है कि इसके द्वारा आए हुए लोग अयोग्य होते हैं। यह झूठ नफरती विचार फैलाए तो हमेशा से जा रहे हैं मगर पहले इसका असर उतना होता नहीं था। मगर अब जब से इनकी सरकार आई है नफरत का असर दिखने लगा है। और अब तो इतना विस्फोटक हो गया है कि अपनी काबिलियत मेहनत से चीफ जस्टिस आफ इंडिया बने बीआर गवई का अपमान करने के लिए उन पर जूता फेंका जाता है। और कोई पछतावा नहीं, माफी नहीं बल्कि उसे उचित ठहराया जाता है। जूते फेंकने वाले के इंटरव्यू धड़ाध ड़ हो रहे हैं। मीडिया उन्हें हीरो की तरह पेश कर रहा है। उत्साहित भक्त ट्रोल और धमकियां दे रहे हैं कि दूसरे जजों के साथ ऐसा होगा। सड़क पर होगा। डर का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज, किसी हाई कोर्ट की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जूता मारने वाले के खिलाफ कुछ बोल सके। और आप पक्का मानिए अगर वह कोर्ट में चला गया कि बार कौंसिल ने उसके वकालत करने पर कैसे रोक लगाई है या बार एसोसिएशन ने उसे कैसे निष्कासित किया है तो उसे तुरंत राहत मिल जाएगी। हो सकता है कोई कोर्ट जस्टिस गवई पर ही टिप्पणी करने की गलती उनकी थी। कुछ भी हो सकता है। जो चाहते थे वह माहौल बना लिया। पहले मुस्लिम के खिलाफ बनाया। मुस्लिम होना ही गुनाह हो गया। उससे जुड़ी हर चीज पर सवाल खड़े कर दिए। खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्तर पर। इसके बाद क्या बचता है? मगर विरोध केवल भारत के मुस्लिम का। भारत के बाहर के मुस्लिम का नहीं। अभी आपने तालिबान सरकार का प्रकरण देखा। इस तालिबान के खिलाफ देश में कितना प्रोपेगंडा चलाया गया। भाजपा से लेकर गोदी मीडिया तक सबने। उद्देश्य उनका विरोध नहीं था। असली मकसद था उनके बहाने भारत के मुसलमानों को बदनाम करना। किसी भी दाढ़ी वाले को देखते ही खासतौर से नौजवान को उसे तालिबानी कहने लगते थे। मगर अब जब तालिबानी आए तो उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में केवल पुरुष पत्रकार जाएंगे इस पर मोदी सरकार को कोई आपत्ति नहीं हुई। उल्टा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसमें महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिए जाने का सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गोदी मीडिया और भक्तों, ट्रोलों वाला यह बचकाना तर्क देने लगे कि अपने दूतावास में वे किसे बुलाएं किसे नहीं यह उनका अधिकार है। एकदम गलत। भारत में भारत के किसी से भेदभाव नहीं होगा का कानून लागू होगा। कल शनिवार को हमने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ट्वीटर फेसबुक पर उन्हें नहीं दोहराएंगे। एक नया उदाहरण। ज्यादातर देशों में जाति का कान्सेप्ट नहीं है तो जातिगत आधार पर भेदभाव का सवाल ही नहीं। लेकिन हमारे यहां एससी एसटी (अत्याचार निवारण) कानून है। अब अगर किसी विदेशी दूतावास के अंदर किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो दूतावास इस आधार पर नहीं बच सकता कि यह तो हमारे यहां अंदर हुआ है। करने वाला और पीड़ित दोनों भारतीय होंगे तो करने वाला भारतीय उस देश की आड़ में बच नहीं पाएगा। बड़ा कानून, प्रिंसिपल लॉ हर जगह लागू होता है। महिला के साथ भारत में कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकता। और साफ कर दें। क्योंकि खुद उन विदेश मंत्री ने कहा है जो भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के हैं। सर्वोच्च पद विदेश सचिव रह चुके हैं। सारे कानून मालूम हैं। यह भी कि कोई भी विदेशी जब भारत में है तो उस पर क्रिमिनल और सिविल सभी मामलों में भारतीय कानून लागू होंगे। एक अनपढ़ दौर आया है कुछ भी बोल दो। नेता बोलते हैं तो वह विदेश मंत्री जयशंकर भी विदेश सेवा से आए हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उद्देश्य एक ही है तालिबान को खुश करना। आखिर एकमात्र दोस्त है। कभी ऐसा पाकिस्तान के साथ होता था। भारत से युद्ध में उसके साथ केवल एक ही देश खड़ा होता था। अमेरिका। आज मोदी जी ने हमारी वह हालत कर दी है कि हमारे साथ अभी पाकिस्तान के साथ संघर्ष में केवल एक ही देश था। यही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार। देश हर मोर्चे पर पीछे जा रहा है। बस केवल नफरत में बढ़ रहा है। मुस्लिम से दलित, दलित से पिछड़ा आदिवासी और उसके बाद बचे कितने? जो बचे हैं सब एक दूसरे के खिलाफ।

चिदंबरम के कहें का क्या है अर्थ ?

बलबीर पुंज

दशकों तक स्वतंत्र भारत की विदेश नीति विदेशी विचारधारा से बंधी रही है। इसी वजह से भारत को बार–बार उन मुल्कों के आगे भी झुकना पड़ा, जो लंबे समय तक भारतीय हितों के खिलाफ खड़े थे। सालों तक भारत ने फिलिस्तीन और इस्लामी देशों का समर्थन किया, जबकि वह कश्मीर के मसले पर मजहब के नाम पर पाकिस्तान का साथ देते रहे। पिछले 11 वर्षों से भारतीय नेतृत्व इस पराजित मानसिकता से मुक्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी ।चिदंबरम के हालिया खुलासे का निहितार्थ क्या है? 17 साल पहले जब वर्ष 2008 में मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित भीषण 26ध्11 आतंकवादी हमला हुआ, जो चार दिनों तक चला, जिसमें सीमापार से आए दस जिहादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतारा और देश का एक बड़ा वर्ग प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता रहाकृ तब तत्कालीन कांग्रेस नीत तत्कालीन संप्रग सरकार (2004–14) विदेशी दबावकृ विशेषकर अमेरिकी नेतृत्व के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिकार स्वरूप कोई भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे हट गई। बकौल चिदंबरम, उस वक्त मेरे मन में आया कि बदला लेना चाहिए।।। मैंने प्रधानमंत्री और बाकी अहम लोगों से इस मामले पर चर्चा की थी, लेकिन निष्कर्ष काफी हद तक विदेश मंत्रालाय और विदेश सचिवों से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, इसकी जगह कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने आगे स्वीकार किया, उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस, मेरे पद संभालने के दो–तीन दिन बाद मुझसे और प्रध ाानमंत्री से मिलने आई थीं।

एनडीए कैडेट अंतरिक्ष की मौत का राज गहराया

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एयरफोर्स कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अंतरिक्ष की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि सीनियर की ओर से लगातार की जा रही प्रताड़ना का नतीजा है। उनका आरोप है कि पुणे पुलिस ने मराठी भाषा में मनमाना बयान लिखकर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। अब परिवार की नजर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर है, जिसमें मामले के खुलासे की उम्मीद है। रविवार को अंतरिक्ष का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर रिटायर्ड सूबेदार मामा अश्वगज सिंह सेंगर ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष बेहद होनहार थे। उन्होंने सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में ही एनडीए की परीक्षा पास कर ली थी। पूरे देश से 2300 कैडेट्स में उनका चयन सेकंड लेफ्टिनेंट पद के प्रशिक्षण के लिए हुआ था। यह सफलता उन्होंने पहली ही बार में हासिल की थी। अश्वगज सिंह के अनुसार अंतरिक्ष को प्रशिक्षण के दौरान एक सीनियर

लगातार परेशान करता था। यह बात उन्होंने घरवालों से भी बताई थी। कंपनी कमांडर से इस बाबत शिकायत की गई थी लेकिन कार्रवाई के बजाय सिर्फ आश्वासन मिला। उत्पीड़न रुका नहीं। उन्होंने कहा कि बार–बार पूछने के बावजूद अधिकारियों ने उस सीनियर का नाम हमें नहीं बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले अंतरिक्ष की मां सीमा सिंह और परिवार के कुछ सदस्य पुणे गए थे। चार दिन तक होटल में ठहरने के दौरान अंतरिक्ष को दो दिन की छुट्टी मिली थी। उसी दौरान उन्होंने सीनियर द्वारा परेशान किए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया था। मामा के अनुसार नौ अक्तूबर शाम पांच बजे अंतरिक्ष ने मां को फोन किया और केवल हाल पूछकर एक मिनट में ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगली सुबह मौत की सूचना मिली। परिवार पुणे पहुंचा तो पता चला कि नौ अक्तूबर की रात वह बिल्कुल सामान्य थे। रात आठ बजे उन्होंने खाना खाया, उसके बाद कैडेट नाइट प्रोग्राम में भाग लिया। वहां गाना गाया और गिटार बजाया। सब कुछ ठीक लग रहा था। परिजनों का कहना है कि रात 10रू30 बजे के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? रिटायर्ड सूबेदार अश्वगज सिंह सेंगर ने बताया कि जब परिवार पुणे पहुंचा, तो अधिकारियों से कई दौर की बातचीत हुई। बार–बार सीनियर का नाम बताने या कम से कम मुलाकात कराने की मांग की गई, लेकिन सेना के अधिकारियों ने नहीं मिलवाया।

मीट का कारोबार करने वाली इंडिया फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर छापा

लखनऊ, (संवाददाता)। संभल में मीट का कारोबार करने वाली इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को छापे मारे। कंपनी के बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एक दर्जन से अधिक शहरों के 30 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला जा रहा है। आयकर विभाग, लखनऊ की जांच इकाई ने यह कार्रवाई की है। छापे की कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी का कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जाता है। कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी अंजाम दिए जाने की शिकायतों के बाद जांच इकाई बीते कई दिनों से सुराग जुटा रही थी। इस बाबत पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद छापे मारकर दस्तावेजी सुबूत जुटाने की कवायद की गई है। आयकर विभाग के 100 से अधिकारी एवं कर्मचारी पीएसी बल के साथ कंपनी के ठिकानों को खंगाल रहे हैं और संचालकों एवं निदेशकों से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग यह भी पता लगा रहा है कि कंपनी द्वारा अनुमति से अधिक पशुओं का कटान तो नहीं किया जा रहा है। दरअसल, बीते वर्षों में मीट कारोबारी कंपनियों के ठिकानों पर छापे के दौरान इसके पुख्ता प्रमाण मिले थे, जिसमें स्थानीय प्रशासन और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई थी। खासकर बरेली की एक कंपनी में तो बड़े पैमाने पर बिना अनुमति पशुओं को खरीदा जा रहा था और उनका कटान कर मीट बेचा जा रहा था।

संक्षिप्त खबरें

सड़क किनारे मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

लखनऊ, (संवाददाता)। 5थाना बंथरा क्षेत्र में रविवार सुबह एक युवक का शव सड़क किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैजानकारी के अनुसार, थाना बंथरा पर वादिनी मंजू देवी पत्नी जगतलाल ने लिखित सूचना दी कि आज सुबह लगभग 6 बजे पक्के संपर्क मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि वह उनका पुत्र जतिन है, जिसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान हैं।मंजू देवी ने बताया कि उनका पुत्र जतिन करीब चार महीने से अपनी पत्नी रागिनी के साथ ससुराल, जनपद उन्नाव में रह रहा था। प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इस संबंध में मु0अ0सं0–353/2025, धारा 281/106(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। मृतक जतिन के शव का पंचायतनामा परिजनों की मौजूदगी में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आयोजन किया

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को रूस के काल्मिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता में निर्माणाधीन भगवान बुद्ध पार्क में माता ग्रीन तारा देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और मंदिर एवं पार्क निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने करुणा और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां ग्रीन तारा से सभी के जीवन में समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना की।उप मुख्यमंत्री मौर्य प्रतिनिधिमंडल के साथ भगवान बुद्ध के अवशेषों को लेकर शनिवार को एलिस्ता पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने गोल्डन एबोड ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध मंदिर परिसर में पवित्र पिपरहवा अवशेषों को प्रदर्शनी हेतु स्थापित किया और मीडिया से संवाद भी किया।उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, करुणा और मानवता का संदेश पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। इस प्रदर्शनी से भारत और रूस के सांस्कृतिक और राजनैतिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। आठ दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान वरिष्ठ भारतीय भिक्षु स्थानीय श्रद्धालुओं से संवाद करेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन करेंगे।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान शाक्य संप्रदाय के प्रमुख, परम पावन 43वें शाक्य त्रिजिन रिनपोछे द्वारा उपदेश और प्रवचन दिए जाएंगे। इसके अलावा, पवित्र 'कंजूर' की प्रस्तुति और बौद्ध कला के खजाने 'बोधिचित्त' की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, राष्ट्रीय संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से 11 से 18 अक्टूबर, 2025 तक एलिस्ता में आयोजित किया जा रहा है।उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि पिपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के अवशेष भारत की सांस्कृतिक चेतना और वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए अत्यंत पूज्यनीय हैं। काल्मिकिया में बौद्ध धर्म केवल धर्म नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है।

निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ बिजलीकर्मियों का आर-पार की लड़ाई का एलान

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने लखनऊ में रविवार को मंथन शिविर का आयोजन किया। इसमें संकल्प लिया गया कि निजीकरण प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके खारिज होने तक लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही दीपावली पर उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली मुहैया कराने का संकल्प लिया गया। इसके लिए 16 अक्तूबर को सभी जिलों में संघ की आमसभा का निर्णय लिया गया। शिविर में अभियंताओं ने अब तक चले आंदोलन पर चर्चा की और पॉवर कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली की निंदा की। कहा, कॉर्पोरेशन प्रबंधन उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कर रहा है। कभी स्मार्ट मीटर तो कभी निजीकरण के नाम पर शोषण किया जा रहा है। इसका भी हर स्तर पर विरोध होगा। निजीकरण के विरोध में आंदोलन और तेज करने का निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से पूर्वांचल व दक्षिणांचल निगमों के निजीकरण के बाद कर्मचारियों दिए जा रहे तीनों विकल्पों पर चर्चा की। इसके बाद सर्वसम्मति से तीनों विकल्पों को खारिज कर दिया गया। संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर, आलोक श्रीवास्तव, जगदीश पटेल आदि ने लखनऊ की व्यवस्था फ्रेंचाइजी के जरिये चलाने की निंदा की। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद सहित अन्य संगठनों ने इसका हर स्तर पर विरोध करने का ऐलान किया है। क्योंकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में उपभोक्ताओं को दिए गए प्रीपेड और पोस्टपेड के विकल्प चुनने के अधिकार में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। इसके बाद भी बिजली कंपनियां संशोधन विधेयक का हवाला देकर उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन कर रही हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 43.44 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। करीब 20.69 लाख उपभोक्ताओं के मीटर को बिना उनकी अनुमति लिए ही प्रीपेड में बदल दिया गया है। विभिन्न निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को यह दलील दी जा रही है कि संशोधित विधेयक में प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर का विकल्प चुनने का अधिकार है। दो दिन पहले जारी संशोधन विधेयक 2025 के प्रस्ताव में इस अधिकार में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ऐसे में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देकर बरगला रही हैं।

सड़क, फुटपाथ पर बने वकीलों के 20 चौंबरों पर चला बुलडोजर

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस व नगर निगम की टीम ने रविवार सुबह पुराने हाईकोर्ट के पास दीवानी कोर्ट के गेट नंबर तीन, डीएम ऑफिस के पीछे वाली सड़क और उसके आसपास फुटपाथ व सड़क पर बनाए अधिवक्ताओं के 20 से अधिक चौंबरों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई सेंट्रल बार एसोसिएशन की मांग पर की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिससे विरोध व हंगामे की नौबत नहीं आई। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी धनंजय कुशवाहा की ओर से बताया गया कि सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के पत्र में बताया गया कि दीवानी न्यायालय परिसर के गेट नंबर तीन और उसके आसपास अवैध निर्माण होने के साथ ठेले व दुकानों का संचालन हो रहा है। जनपद न्यायालय की दीवार से सटाकर चौंबर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अधिवक्ताओं, वादियों को पार्किंग व आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए रविवार सुबह सात बजे पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। नगर निगम जोन एक की टीम भी संसाधनों के सा कुछ चौंबर अब भी मौजूदरू डीएम ऑफिस के पीछे वाली सड़क पर ल चार चौंबर तोड़े गए, लेकिन 15 अब भी बने हैं। इनमें से एक पार्षद का बताया जा रहा है, जिस पर बुलडोजर नहीं चला। स्वास्थ्य भवन तिराहे से डीएम ऑफिस वाली सड़क पर आधा किमी के फुटपाथ पर अधिवक्ताओं के चौंबर हैं। यह फुटपाथ स्मार्ट सिटी योजना में कई करोड़ रुपये खर्च कर बनाया गया था। फुटपाथ खाली नहीं है और सड़क पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिससे दिनभर जाम सी स्थिति रहती है। पूर्व मंडलायुक्त ने कई बार इन कब्जों को लेकर सवाल उठाया, पर अधिवक्ताओं का मामला होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी धनंजय कुशवाहा का कहना है कि कब्जे नगर निगम ने हटाए। पुलिस सहयोग में रही। प्रकाश सिंह का कहना है कि अभियान पुलिस का था। इसमें नगर निगम की टीम संसाधनों के साथ रही।

संक्षिप्त खबरें

समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर राजधानी सहित प्रदेशभर में श्रद्धांजलि

लखनऊ। समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मनाई गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लोहिया जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित डा. लोहिया पार्क में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त लोहिया संस्थान गोमतीनगर और चौक स्थित लोहिया पार्क में भी उनके चित्र और प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोमतीनगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचकर डॉ. लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे।श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया जी ने जीवन भर गैरबराबरी, भेदभाव, अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए सप्तक्रांति का आह्वान किया। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी लोग आज भी लोहिया जी के विचारों और सिद्धांतों पर चलकर नाइंसाफी, भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे।अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर प्रदेश में भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, जातीय उत्पीड़न और कानून–व्यवस्था की विफलताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाकर आम जनता और किसानों के हितों की उपेक्षा कर रही है।इस अवसर पर लोहिया पार्क में युवा कार्यकर्ताओं और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने "डा. लोहिया अमर रहे, अखिलेश जी जिंदाबाद" के नारों के साथ हिस्सा लिया।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस का जोरदार हमला

लखनऊ, (संवाददाता)। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉ. सी.पी. राय ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लाकर देश की जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत साधन प्रदान किया था। इस कानून के माध्यम से नागरिकों ने अपने तमाम मसले हल करवाए, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे कमजोर कर दिया और तब से जनता को अपने अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं।डॉ. राय ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुँच प्रदान करना था, ताकि शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हो। यह कानून विशेष रूप से समाज के हाशिए पर बसे लोगों के लिए जीवनरेखा साबित हुआ और उन्हें राश, पेंशन, बकाया मजदूरी और छात्रवृत्तियों जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुँच प्रदान की।

छूट के साथ कारों व प्रॉपर्टी की बुकिंग

लखनऊ, (संवाददाता)। विभूतिखंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमर उजाला की ओर से हुए दो दिवसीय प्रॉपर्टी एंड ऑटो एक्सपो के अंतिम दिन रविवार को स्टॉलों पर खूब भीड़ रही। विभिन्न योजनाओं के तहत एलडीए अपने फ्लैटों की खरीद पर दो लाख तक की छूट दे रहा है। एल्डिको, रिशिता डेवलपर्स, नीलांश ग्रुप, साहू सिटी पर्ल व ओमैक्स के स्टॉलों पर भी ग्राहकों ने फ्लैटों के रेट जाने। ऑटो एक्सपो में ह्यूंडई की एक्स्टर कार डिमांड में रही। 10 कारों की बुकिंग और 150 एन्क्वॉयरी हुई। इसी तरह मारूति सुजूकी के आकर्षक ऑफर के लिए भी लोगों ने 100 से ज्यादा एन्क्वॉयरी की और कई कारों की बुकिंग कराई। एक्सपो में रॉयल कैफे रिफ्रेशमेंट पार्टनर रहा। ऐसे एक्सपो में ग्राहकों के लिए रेट की तुलना करना आसान हो जाता है। मारूति सुजुकी की कई कारों की बुकिंग हुई और 100 से ज्यादा पूछताछ हुईं। जीएसटी की वजह से एक लाख तक कारें सस्ती हो गई हैं। इसके बाद मारूति सुजुकी अलग–अलग कारों पर 60–70 हजार रुपये का ऑफर भी दे रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो में होना एल्डिको के लिए गौरव की बात है, क्योंकि 1985 से एल्डिको अपने ग्राहकों के साथ जुड़ा हुआ है। समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता पूर्ण निर्माण के लिए अवॉर्ड भी मिला है। आईआईएम रोड पर एल–2, स्काईवॉक, ट्विन टॉवर्स, गोमतीनगर एक्सटेंशन में एल्डिको ट्रिनिटीऔर हैंगिंग गार्डेंस प्रमुख प्रोजेक्ट हैं। सीओओ, एल्डिको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड त्योहारी सीजन में एलडीए विशेष छूट दे रहा है। भूखंडों में लोगों की काफी रुचि रही। ऐसे एक्सपो लखनऊ वासियों के लिए अच्छी पहल है। अधिकतम दो लाख तक की छूट है जबकि ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में लोगों ने रुचि दिखाई। – प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण साहू सिटी पर्ल ग्रैंड फेस्टिव सीजन 3.0 में फ्लैट्स की बुकिंग पर चार लाख तक के आकर्षक लाभ की सुविधा दे रहा है। शानदार लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं के साथ हरे भरे परिसर में 61.43 लाख से 85 लाख रुपये के फ्लैट हैं। निवेश का अच्छा मौका है। – निशांत वर्मा, हेड एसएलडी (सेल्स एंड मार्केटिंग) एक्सपो में हमें ब्रांड एक्सपोजर मिला। शाम को अच्छा फुटफाल रहा जिसमें सबसे ज्यादा पूछताछ सोलर एसी की रही। बिजली की बचत के साथ इकोजेन कंपनी सोलर आटा चक्की, फ्रीजर के साथ साथ सोलर एसी भी लाई है। सरकारी सब्सिडी की भी व्यवस्था है। एजीएम, इकोजेन सोलर ऐसे आयोजन ग्राहक और संस्थान के बीच की दूरी कम करते हैं। त्योहारों पर अच्छी छूट दे रहे हैं। रिक्त आवासीय व अनावासीय संपत्तियों को ई–नीलामी में लेने का सुनहरा अवसर है। वृंदावन योजना लखनऊ में आईटी सिटीध्आईटी भूखंड उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश एक्सपो में ह्यूंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सटर की सबसे ज्यादा पूछताछ हुईं। 10 कारों की बुकिंग हुई जबकि 150 पूछताछ हुईं। शहर के लिहाज से एक्स्टर को बहुत पसंद किया गया। एक हफ्ते बाद दिवाली है तो इसलिए भी ग्राहक अब ज्यादा इंतजार न करके सीधा बुकिंग करा रहा है। – गौरव चौहान, रीजनल मैनेजर, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ओमैक्स ग्रुप ग्राहकों की पहली पसंद है। रायबरेली रोड स्थित प्रीमियम प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ–साथ अयोध्या में भी यूपीएसआरटीसी के साथ मिलकर बी टुगेदर सेंटर पॉइंट बन रहा है। होटल, सुइटस, रिटेल शॉप, बैंक्वेट, फूडकोर्ट और मल्टीप्लेक्स लेकर सबकुछ। आवास के लिए अपार्टमेंट कसीया प्रोजेक्ट में हैं। सीनियर वीपी एंड बिजनेस हेड, ओमैक्स लिमिटेड आधुनिक सुविधाओं के साथ नीलांश सेलेस्ट के फ्लैट ओपन एरिया की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बन रहे हैं। ओपन एरिया में फ्लैट कल्चर को पसंद करने वाले ग्राहकों ने एनक्वॉयरी की है। 72 प्रतिशत ओपन एरिया वाले इस प्रोजेक्ट में 615 फ्लैट हैं। वह भी शहर के बीचो बीच जहां से चारबाग, हजरतगंज व एयरपोर्ट कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं। एक्सपो में हिस्सा लेना हमारे लिए खास है, क्योंकि ग्राहकों तक अपने प्रोजेक्ट्स की विशेषताओं को पहुंचाया। हमारे रिशिता मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 1100 पजेशन कंप्लीट हो चुके हैं और रिशिता मलबरी हाइट्स प्रोजेक्ट में 675 पजेशन ऑफर किए जा चुके हैं। 435 रजिस्ट्री हो चुकी है। बहुत जल्द नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। एक्सपो में संभावित ग्राहकों के अलावा ब्रांड एक्सपोजर भी मिला। ग्राहकों को हमने सरकारी सब्सिडी और कंपनी के विशेष ऑफर के बारे में बताया।

सूचना का अधिकार कानून की 20वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की प्रेसवार्ता

लखनऊ, (संवाददाता)। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केन्द्र सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री डॉ. सी.पी. राय ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था, जिसने शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।डॉ. राय ने बताया कि यह कानून आम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इस अधिनियम के जरिए देश के सबसे वंचित वर्गों को राशन, पेंशन, मजदूरी और छात्रवृत्ति जैसे अधिकार दिलाने में मदद मिली। लेकिन 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने इस कानून की स्वतंत्रता को लगातार कमजोर किया, जिससे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे को गहरी क्षति पहुँची है।उन्होंने कहा कि 2019 में किए गए संशोधनों ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार किया, क्योंकि अब उनके कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है। वहीं 2023 में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने ''व्यक्तिगत जानकारी'' की परिभाषा को इतना व्यापक बना दिया कि अब सार्वजनिक हित से जुड़ी सूचनाएं भी छिपाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार और सरकारी खर्चों की निगरानी की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ा है।डॉ. राय ने कहा कि देश के केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्थिति आज बेहद चिंताजनक है। 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो आयुक्त कार्यरत हैं और सितंबर 2025 से मुख्य आयुक्त का पद भी रिक्त है। देश भर में चार लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जबकि केवल केन्द्रीय आयोग में 23 हजार से अधिक मामले पेंडिंग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के खर्च, कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की संख्या और पीएम केयर्स फंड के उपयोग जैसी जानकारियां आरटीआई के तहत मांगे जाने पर भी सार्वजनिक नहीं की गईं।डॉ. राय ने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि पारदर्शिता के लिए संघर्ष करने वाले कई कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, जैसे भोपाल की शहला मसूद और महाराष्ट्र के सतीश शेट्टी, जो भ्रष्टाचार और अवैध खनन को उजागर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे आरटीआई उपयोगकर्ता असुरक्षित हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम की धारा 44(3) की समीक्षा की जाए और आयोगों में रिक्त पदों को पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया से भरा जाए। साथ ही आयोगों की कार्यकुशलता और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए ताकि पत्रकारों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और महिला प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलेडॉ. राय ने कहा कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं बल्कि नागरिक सशक्तिकरण और लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी है।प्रेसवार्ता में प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉ. सुधा मिश्रा ने दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को रोकने की घटना की निंदा की और कहा कि भारत की धरती पर आधी आबादी का यह अपमान अस्वीकार्य है। इस अवसर पर मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, प्रवक्ता डॉ. उमाशंकर पांडेय, डॉ. सुधा मिश्रा, सचिन रावत, आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव तथा जैनब हैदर उपस्थित रहीं।

गलत दिशा से आ रही कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। समेसी पावर हाउस के पास शनिवार को बाइक सवार अतुल शुक्ला (38) की गलत दिशा से आ रही कार से टक्कर हो गई। हादसे में अतुल की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया। रविवार को मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने समेसी बाजार में अतुल का शव रखकर डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन भी किया। समेसी निवासी अतुल के पिता सत्यदेव शुक्ला के अनुसार बेटा मोहनलालगंज के गौरा स्थित सूर्या इंस्टिट्यूट में गार्ड था। शनिवार को अतुल ड्यूटी कर रात को बाइक से घर लौट रहे थे। नगराम–निगोहां मार्ग पर समेसी पावर हाउस के पास गलत दिशा में आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अतुल छिटक कर दूर जा गिरे और सिर में गंभीर चोट लगी। खबर पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी व बेटा हैं। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन अतुल का शव लेकर समेसी बाजार पहुंचे और शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन लोगों ने अतुल के घरवालों को मुआवजा और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है और कार भी जब्त कर ली गई है। मुआवजे के लिए एसीपी ने तहसीलदार से परिजनों की बात कराई। अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद घरवाले शांत हुए और प्रदर्शन खत्म हुआ।

42 लाख रुपए के गबन के आरोप जेई,ग्राम प्रधान और सचिव पर ग्रामीण धरने पर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,14 अक्टूबर ।सिरकोनी विकास खंड की ग्राम पंचायत विशुनपुर मझवारा में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपये के गबन का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता रमेश कुमार चौबे ने ग्राम प्रधान, सचिव और जेई पर मिलीभगत कर बिना कार्य कराए ही वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 में कुल 42.33 लाख रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

रमेश कुमार चौबे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में चक के समतलीकरण और मेड़बंदी के नाम पर फर्जी भुगतान किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 जून 2025 को 1,58,760 रुपये का भुगतान बिना किसी कार्य के किया गया। इसी तरह, गवाह हरिनाथ और इनराज के चक के समतलीकरण और मेड़बंदी के लिए 17 जुलाई 2025 को 98,784 रुपये का फर्जी भुगतान किया गया।शिकायतकर्ता ने बताया कि अगस्त 2025 तक इसी वित्तीय वर्ष में अन्य 17 लोगों के चक के समतलीकरण और मेड़बंदी के नाम पर कुल 19,18,456 रुपये का फर्जी भुगतान किया गया। आरोप है कि कुछ मामलों में बिना कार्य के ही भुगतान कर दिया गया, जबकि कुछ अन्य मामलों में केवल कुछ मजदूरों को लगाकर फोटो खींचकर और मामूली खर्च कर कागजी खानापूर्ति की गई। इन सभी भुगतानों की सूची प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी कुल 20,57,000 रुपये के गबन का आरोप है। यह राशि सात विभिन्न कार्यों (बंधा एवं समतलीकरण) के नाम पर भुगतान की गई थी। रमेश कुमार चौबे ने दावा किया कि इन सभी कार्यों पर मनमाने और फर्जी तरीके से भुगतान किया गया। कागजों में बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर दिखाया गया, जबकि मौके पर केवल कुछ मजदूर लगाकर फोटो खींचकर कागजी कोरम पूरा किया गया और फर्जी भुगतान किए गए। मौके पर पहुंचे परियोजना निदेशक ,डीसी मनरेगा ,और सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह ने धरना स्थल पर पहुंच कर पीड़ित की आश्वाशन दिया कि दो दिन में उनको जांच रिपोर्ट मिल जाएगी यदि वो संतुष्ट नहीं है तो जिलाधिकारी से अपनी बात रख सकते हैं।

बिना अनुमति पटाखा रखने के आरोप में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज,20 कुंतल अवैध आतिशबाजी सीज रू पुलिस अधीक्षक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । जनपद में दीपावली से पहले पटाखों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सक्रिय रूप से अवैध रूप से संचालित घरों के अंदर संचालित पटाखे की दुकानों पर लगातार चेकिंग की जा रही है।इस संबंध में मंगलवार को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि बिना अनुमति के रिहायसी क्षेत्र में आतिशबाजी रखने के सम्बन्ध में कुल 04 अभियोग पंजीकृत किया गया है, लगभग 20 कुंतल अवैध रूप से प्राप्त आतिशबाजी को पुलिस द्वारा सीज किया गया है। फायर विभाग के माध्यम से आतिशबाजी के सामान रखने की जगह का परीक्षण कराया जा रहा है। 14 लोगों द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके लाइसेंस के निलंबन हेतु पत्राचार किया गया है। फायर ब्रिगेड द्वारा केमिकल फायर से होने वाले घटनाओं के संबंध में स्कूलो, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

पुलिस ने तमंचे व कारतूस के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जफराबाद थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को पुलिस ने एक बदमाश को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।बदमाश को काफी दिनों से पुलिस पकड़ने के लिए लगी हुई थी।

मुखबिर से मिली सूचना पर प्रशिक्षु सीओ शुभम वर्मा थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल व चौकी प्रभारी राधेश्याम सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए।वहां पर पुलिस की टीम ने घेरेबंदी किया।पुलिस की टीम को देखकर एक युवक भागने लगा।पुलिस ने उसे दौड़ा लिया और थोड़ी दूर जाते जाते उसे दबोच लिया।तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ।इस मामले में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश शाहरुख पुत्र अब्दुल जब्बार सरायख्वाजा क्षेत्र के जपटापुर गांव का रहने वाला है।इसके ऊपर आधा दर्जन लूट,छिनैती,आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है।यह काफी शातिर अपराधी है।इनमें तीन मुकदमे आजमगढ़ जिले में पंजीकृत है।

खाद्य विभाग में छापा मार कर लाखों रुपए के मिठाईयों को किया जब्त,कई नमूने जाँच हेतु भेजे प्रयोगशाला

अयोध्या।मंगलवार को दीपावली के साथ–साथ अन्य पर्वो को देखते हुए खाद्य विभाग मिठाइयों के साथ–साथ अन्य खाद्य पदार्थों को बेचने वाले विक्रेताओं पर छापा मार मारकर संदिग्ध दिखाई देने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया और कुछ को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मानिक चंद्र सिंह ने बताया के त्यौहार को देखते हुए इनके द्वारा गठित टीमों द्वारा चेकिंग तो की ही जा रही है साथ ही साथ जिले के विभिन्न एसडीएम तथा उनके नेतृत्व में खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मानिकचंद ने बताया कि मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सोनी, नन्द किशोर यादव के द्वारा आर0के0 ट्रेडर्स, हलकारा का पुरवा, अयोध्या से रंगीन चीनी खिलौना,रामघाट चौराहा से नमूना रंगीन चीनी खिलौना, गट्टा 125000ध्– रूपये का रंगीन चीनी खिलौना का जब्त किया गया।सन्तोष कुमार साहू के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी,सुमित चौधरी, शरद पाल के द्वारा श्रीराम जनरल स्टोर, गद्दोपुर, अयोध्या से बेसन, बैकिंग पाउडर एवं गणेश जनरल स्टोर, वजीरगंज से 01 नमूना वनस्पति लिया गया मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 पी0के त्रिपाठी के नेतृत्व में अनूप सिंह,विवेक कुमार मौर्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सौरभ स्वीट्स से नमूना खोआ, नमूना सोनपापड़ी,नमूना बत्तीसा, बीकापुर से नमूना गुड़ का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजा गया। उन्होंने बताया कि जिनकी जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान, परंपरा के लिए करें प्रेरितः स्वांत रंजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,14 अक्टूबर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महंत अवेद्यनाथ संगोष्ठी भवन में विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में "भारतीय ज्ञान परंपरा" विषय पर मंगलवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयामोंकृशिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और नैतिकता पर विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वांत रंजन ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपने विद्यार्थियों को सदैव सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, आत्मत्याग और देशभक्ति जैसे गुणों की शिक्षा देने की बात की थी। यह गुण भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा हैं और चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद 'बिस्मिल' का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के लिए कार्य करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है और नई पीढ़ी को भी इसी भावना से प्रेरित होना चाहिए। मुख्य वक्ता, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रधानमंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य आत्मचेतना को जागृत करना है। उन्होंने महाराणा प्रताप की तलवार और सबरी माला के पंचधातु दर्पण का उल्लेख करते हुए भारतीय कारीगरों की वैज्ञानिक दक्षता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं जब आंगन में तुलसी लगाती थीं, तो वह केवल आस्था का नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक था। प्रो. पांडे ने कहा कि "गुरु में अग्नि भाव होना चाहिए। शिक्षा कभी केवल परीक्षण या पुस्तकों का विषय नहीं, बल्कि ज्ञान का विषय होना चाहिए।" उन्होंने कुल परंपरा और गुरुकुल परंपरा को भारतीय शिक्षण प्रणाली की जड़ बताया।

लगाये गये वृक्षों की फोटो सहित आख्या उपलब्ध करायें– जिलाधिकारी'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मंगलवार को जिला वृक्षोरापण, जिला पर्यावरण एवं जिला गंगा समिति की बैठक जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानन्द सभागार में आहूत की गयी। बैठक में जिला वृक्षारोपण के तहत जनपद स्तरीय विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि लगायें गये वृक्षों में कितने जीवित है उनकी गणना करते हुए फोटो सहित सत्यापन आख्या तत्काल उपलब्ध करायें। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण करने वाले विभागाध्यक्षों से कहा कि वृक्षारोपण के बाद उन वृक्षों की सुरक्षा, सिंचाई एवं संरक्षण के सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये है उसकी जानकारी भी उपलब्ध करायें। जिला गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत गंगा किनारे के गांवों में डोर टू डोर अभियान चलाकर कूड़ा निरस्तारण कराएं तथा गंगा किनारों पर सफाई अभियान चलाकर सफाई करायें। उन्होने कहा कि गंगा में किसी भी नाले का प्रवाह न होने दिया जाये और वायो मेडिकल वेस्ट का मुख्य चिकित्सा अधिकारी निस्तारण करायें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, प्रभागीय निदेशक जेबी सैन्डे, अपर जिलाधिकारी विध्रा प्रियंका सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट डॉ अरुणिमा श्रीवास्तव, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, जिला गंगा समिति के अशोक कुमार सिंह सहित अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

'एन आर एल एम द्वारा एक दिवसीय बैंकर्स कार्यशाला का हुआ आयोजन'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जनपद हरदोई में संचालित स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला में सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी द्वारा किया गया जिसमें अच्छे कार्य करने वाले शाखा प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं बैंक सखी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यशाला का समापन मुख्यविकास अधिकारी द्वारा किया गया साथ में उपायुक्त स्वतः रोजगारध्ध डिप्टी कलक्टर भूमिका यादव उपस्थित रहीं।

काफी दिनों से कैंट क्षेत्र मे दहशत बना तेंदुआ के जाल में फंसने के चलते क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस

अयोध्या।मंगलवार की भोर में कई दिनों से थाना कैंट क्षेत्र के माझा,सहादतगंज वह सर्दियों के कछार सहित अन्य क्षेत्र में विचरण कर रहा तेंदुआ कैंट क्षेत्र में लगी जाली में फंस ही गया। जैसे ही आसपास के क्षेत्र में यह खबर फैली तो आसपास के लोगों में सुकून का माहौल दिखाई दिया क्योंकि यह पिछले दो महीनों से स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां आसपास विचरण करता रहता था।इसको लेकर कई बार कैंट पुलिस के साथ–साथ वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वन विभाग की चंगुल में नहीं आया।मंगलवार सुबह 6 बजे तेंदुआ आर्मी की ओर से कैंट क्षेत्र में लगाई गई लोहे की जाली में फंस गया।जाली से निकलने की उसने काफी कोशिश किया।वह करीब 1 घंटे तक जाली से निकलने को छटपटाता रहा।जाली मे फसें होने के चलते तेदुंआ उग्र होकर जाली पर जोर–जोर से टक्कर मारता रहा। थकने के बाद कुछ देर के लिए बैठ जाता।यह सिलसिला काफी देर तक चला।भोर के समय इधर से गुजरने वाले लोग जब तेंदुए की दहाड़ सुनी तो डर भी गए और जब मौके पर देखा तो पाया कि तेंदुआ जाल में बंद होने के चलते दहाड़ रहा था। जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुंरत पुलिस और वन विभाग को दी।सूचना पर आर्मी के जवानों के साथ वन विभाग की टीम पहुंच गई।पूरे इलाके को सील कर दिया गया।लखनऊ से पहुंची टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया।5 घंटे तक तेंदुआ जाली मे फंसा रहा।डीएफओ प्रखर गुप्ता ने बताया कि ट्रैकुलाइज करने के लिए लखनऊ से टीम को बुलाया गया था।टीम ने तेंदुए को ट्रेंकुलाइज कर दिया है।वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में सुरक्षित कैद कर दिया है।तेंदुए को लखनऊ चिड़िया घर भेजा जाएगा।बताया कि लोहे की जाली में फंसने से तेंदुए के एक पैर में चोट लगी है।डॉक्टर्स उसका उपचार कर रहे हैं।

मुस्लिम महिलाओ द्वारा बनाये गए दीपक ,अमेरिका में जलेंगे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। दीपावली का त्यौहार करीब आते ही,जौनपुर में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाएं दीपोत्सव के महत्वपूर्ण त्यौहार पर अपना योगदान दे रही हैं।जलालपुर के महिमापुर गांव में जौनपुर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश हो रही है। मिल्की स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष जफरून एजाज अपने 7 मुस्लिम और 5 हिन्दू कुल 12 सदस्यों के साथ मिलकर आकर्षक और अलौकिक लगभग दो घंटे जलने वाला मिट्टी ,मोम का दिया बना रही हैं। उन्होंने कहा कि दिए भारत मूल के अमेरिकी निवासी प्रकाश खिलानी जो 3 वर्ष से उक्त दिए की मॉग कर रहे थे। इस वर्ष मार्च के महीने में भारत आए थे और लखनऊ के बन्धन होटल से मेरे पति एजाज अहमद द्वारा अमेरिकन डॉलर देकर दीया ले गए अध्यक्ष को इस बात का बड़ा हर्ष और गर्व है कि अपने देश की मिट्टी की पूजा दीए के रूप में अमेरिका में किया जाएगा ।समूह अध्यक्ष ने बताया कि दीया भी अपने हो ग्राम संगठन के जय मा दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सदस्य से बनवाती है। और उसके बाद 7 स्टेप में और 13 आईटम को मिलाकर उक्त दीया तैयार किया जाता हैं। तब जाकर इसमें खूबसूरती आती हैं ये हम महिलाओं के लिए बड़ी बात हैं कि अधिकारी इस दियो की मांग कर रहे और इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है अब लोग उत्तर प्रदेश मुख्यालय जाते है तो जौनपुर से दीया ले जाते है यह दीया दिवाली के अलावा अब लगभग हर महीने बिकता रहता हैं ये हमारे महिमापुर गांव के लिए गर्व की बात है कि उक्त दीया ने पूरे जिले का मान बढ़ाया है. उक्त दीया उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों में मिशन निदेशालय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन द्वारा चुना गया है।इस बार दीए स्टाल यू पी ट्रेड शो स्वदेशी मेला में बी आर पी कॉलेज मैदान में 14 से 18 अक्टूबर को लगाया जाएगा।

तिरंगे रंग में रंगा दीपक , बना आकर्षण का केंद्र

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत मुस्लिम महिलाएं भी बिना तेल से जलने वाले मिट्टी के दीपक में मोम से बने रंग बिरंगे व तिरंगे के कलर में दीपक बनाने का कार्य कर रही हैं।इस बार का दीपावली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों से स्वदेशी अपनाओ का आह्वान किया है। महिलाओ के द्वारा भारत के तिरंगे के रंग का दीपक बनाया जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसकी खरीददारी भी कर रहे है। स्वयं सहायता समूह को लीड कर रही जफरून एजाज बताती है कि हमारे समूह का नाम मिल्की स्वयं सहायता समूह है, इस समूह में 10 महिलाएं कार्य करती है,जो सुबह 11 से कार्य शुरू करती है और शाम 5 बजे तक सभी मिलकर कार्य करती हैं। जिसमे ज्यादातर मुश्किम समाज(जफरून एजाज,रिहाना,चांद तारा,नजबुन,सोफिया,जौहरी,इंदु बाला,बिशाखा,सुभावती,सीमा)से आती हैं।जफरून एजाज ने बताया कि हम सभी महिलाएं पिछले तीन वर्ष से यह कार्य कर रहे हैं, दीपावली को ध्यान में रखते हुए बनाया है, लगभग अभी 15 हजार से ज्यादा दियों का आर्डर है।जौनपुर से ही नही मुंबई से भी इसका आर्डर मिला है।जब से हम लोग यह कार्य कर रहे हैं हर वर्ष इनकम में बढ़ोतरी हो रही है।जहां पहले वर्ष में मात्र एक हजार दिए बनाये थे,लेकिन अब 15 हजार से अधिक दिये बना रहे हैं।हम सभी महिलाओं की इनकम लगभग दस हजार प्रति महिला हो जाती है। पहले इस कार्य को हम लोगो ने अपने बचत के रूपयों से शुरुआत की थी,उसके बाद सरकार की तरफ से एक लाख दस हजार रुपए की मदद मिली जिसे हम लोगो ने इस कार्य मे लगाया।उन्हीने बताया कि जो मिट्टी का दीपक है उसे हम लोग एक दूसरे समूह से खरीदते हैं जिससे उसकी भी इनकम हो जाती है।सरकार की स्वदेशी अपनाओ की पहल बहुत अच्छा है और यह दीपक पूरी तरह से स्वदेशी है।इसमे किसी तरह की कोई मशीनरी कार्य नही करती है यह शुद्ध स्वदेशी गांव की महिलाओं के हांथ का बना दीपक है।इसमे मिट्टी का दीया, मोम और कलर का उपयोग किया जाता है।इन्होंने इस बात की खुशी जताई कि उनके शौहर के दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं उनको यह दीपक बहुत पसंद आया,वह सैम्पल के तौर पर 50 दीपक लेकर गए हैं।उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली पर वह अमेरिका में जलाएंगे।जाफरून ने बताया कि यह दीपक एक से डेढ़ घंटे तक जलता है।एक दीपक 15 रुपये का बिकता है, लेकिन 12 दियो का एक पैकेट 150ध्– रुपये में बेचते हैं।जिस पर 200 रुपये का एमआरपी लिखा है।मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने का आहवान किया है इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया है।अपने देश की चीजों का उपयोग अपने ही देश मे करें।

शालीमार ग्रुप ने कर्मचारियों के लिए मैक्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर किया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

लखनऊ।, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, शालीमार ग्रुप ने आज अपने हेड ऑफिस में मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और निवारक जांच को बढ़ावा देना रहा। इस हेल्थ कैंप में 100 से अधिक कर्मचारियों और सहयोगियों ने हिस्सा लिया। आयोजित शिविर में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी पर फोकस किया गया, जिसमें ओपीडी परामर्श और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की सुविधा दी गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हड्डियों के स्वास्थ्य, पोषण और व्यायाम से जुड़ी अहम जानकारी भी साझा की। शालीमार ग्रुप की ओर से कहा गया कि इस तरह की पहल न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है बल्कि उन्हें सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। इस अवसर पर शालीमार समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री खालिद मसूद ने कहा, ष्शालीमार सिर्फ घर नहीं बनाता, बल्कि उन लोगों से भी जुड़ा है जो इन घरों में जीवन बसाते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाना हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

पूर्वांचल युवा महोत्सव का आयोजन 23,24एवं 25 अक्टूबर को बी आर पी इंटर कॉलेज के मैदान में - दिनेश तिवारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर पूर्वांचल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्वांचल युवा महोत्सव का आयोजन बी.आर.पी. इंटर कॉलेज के मैदान में 23, 24 एवं 25 अक्टूबर 2025 को अपरान्ह 1:00 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक बी आर.पी. इंटर कॉलेज जौनपुर के मैदान में संपन्न होगा। पूर्व में यह आयोजन नवदुर्गा मंदिर, विसर्जन घाट पर संपन्न होना था किंतु कलाकारों के अनुरोध तथा छठ पूजा को दृष्टिगत रखते हुए यह आयोजन बीआर पी इंटर कॉलेज के मैदान, पर संपन्न होगा ,जिसमें पूर्वांचल ही नहीं वरन प्रदेश के विशिष्ट कलाकारों को अपने प्रतिभा को प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जनपद एवं पूर्वांचल के नवोदित कलाकारों का ऑडिशन 7,8 एवं 9 अक्टूबर 2025 को मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय में संपन्न हो चुका है और कलाकार अपनी प्रतिभा प्रस्तुति के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं। पूर्वांचल युवा महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस महोत्सव में सहभागिता करने के लिए दूर–दूर से निरंतर कलाकारों के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।